श्री नन्द किशोर यादव: सर, पुलिस की फॉयरिंग में 5 लोगों की मौत हुई, जिनका आज वहां पर पोस्टमार्टम हो रहा है ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: अब आप समाप्त कीजिए, आपको दोबारा टाइम दिया गया है।

श्री **नन्द किशोर यादव**: इसके अलावा जो 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उनको बनारस रेफर किया गया है। पुलिस अत्याचार की यह घटना लगातार हो रही है — चंदौली में 4 लोगों को मारने का काम किया, मऊ में 5 लोगों को मारने का काम किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस निरंकुश हो गई है, सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि इस मामले में वह हस्तक्षेप करे और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो निरंकुश हो गई है, उसको नियंत्रित करने का काम करे।

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Sir, I associate myself with this subject. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You just associate yourself with it. Don't speak on it. *...(Interruptions)...* Please don't speak. *...(Interruptions)...*

SHRI KAMAL AKHTAR: Sir, I associate myself with it. *...(Interruptions)...*

श्री गंगा चरण: उपसभापति जी, मुझे स्पष्टीकरण देने का मौका दीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं है, रूल्स में नहीं है ...(**व्यवधान**)... मैंने कहा है कि आप नोटिस दीजिए ...(**व्यवधान**)...

Shortage of pulses in the country

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर यहां यह प्रश्न उठा रहा हूं। इस समय देश भर में उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बड़ी तेजी के साथ बढ़े हैं, विशेषकर खाद्यान्न वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, सब्जी के दाम तो आसमान छूने लगे हैं। दाल एक-दो सप्ताह पहले जहां 78 रुपए किलो या 80 रुपए किलो थी, आज वह 100 रुपए किलो हो गई है। जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें ध्यान में आई हैं, जो कुछ चीजें सामने प्रस्तुत की गई हैं, उनमें कोलकाता बंदरगाह के खिदीरपुर डॉक के जिस हिस्से में दाल मंगाई गई थी और इंटरनेशनल मार्केट से बकायदे तीन साल पहले यानी 2007 में 15 लाख टन दाल मंगाई गई थी। वहां से दाल आ भी गई और दाल आ जाने के बाद बोरे में वहां पड़ी रही, वहां कोई नहीं गया। वहां दाल सड़ती रही, लोग पैरों से उसे रौंदते रहे, लेकिन वहां से दाल उठाई नहीं गई। लोग बता रहे हैं कि यह जूतियों में बंट गई। हालत ऐसी निर्माण हो गई कि जिस सरकार ने दाल को मंगाया, उस सरकार ने, उस विभाग ने यह ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस की कि सही मायने में दाल का आयात किया गया है, काफी मात्रा में किया गया है और उसको देखा जाए, उसको बाजार में लाया जाए, आम उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाए, इसकी चिंता नहीं की गई। इससे हालात ऐसे पैदा हो गए कि जब कुछ पत्रकार बंधुगण गए, तो लोगों को लगा कि वहां कुछ हो रहा है। वहां पर लोग गए। वहां दाल इस प्रकार से पैरों के नीचे पड़कर पिस गई थी, सड़ गई थी और पानी पड़ने के कारण इतनी सड़ांध हो रही थी कि वहां पर नाक को दबाकर जाना पड़ा। उसको देखने के बाद लोगों को लगने लगा कि यह क्या है? जब खोल कर देखा गया, तो पता लगा कि यह दाल है। यह दाल 2007 में मंगाई गई थी। अगर इस प्रकार की प्रशासनिक उदासीनता बनी रही और इस ढंग से काम करने का हिसाब चलता रहा, तो निश्चित रूप से आम उपभोक्ता और आम आदमी की जो बात कही जा रही है, आम आदमी को जो राहत देने की बात कही जा रही है, यह केवल * है, यह केवल मिथ्याचारिता है और यह आम आदमी की जिंदगी के साथ * करने की साजिश चल रही है। जिनके द्वारा या जिन अधिकारियों के द्वारा इस तरह की हरकत की गई है, जिसके कारण आज मंहगाई आसमान छूने लगी है, ऐसे लोगों के विरुद्ध बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सामान्य उदासीनता नहीं बरती है, बल्कि उन्होंने ऐसी उदासीनता बरती है, जो

*Not recorded.

क्षम्य नहीं है। उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें तत्काल हटा देना चाहिए। महोदय, सदन से मेरी इतनी ही मांग है। धन्यवाद।

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला (राजस्थान): महोदय, मैं अपने आपको इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करती हूँ।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं अपने आपको इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करती हूँ।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): महोदय, मैं अपने आपको इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

Inappropriate air fare being charged on Delhi-Dharmashala sector

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहती हूँ। महोदय, दिल्ली से धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) जाने और आने के लिए केवल किंगफिशर एयरलाएंस अपनी सेवा प्रदान करती है। प्रतिदिन एक फ्लाइट दिल्ली से धर्मशाला जाती है और वही फ्लाइट धर्मशाला से दिल्ली आती है। महोदय, सभी जानते हैं कि धर्मशाला एक पर्यटक गंतव्य है और हिमाचल के लोगों के साथ-साथ देश-विदेश से आने वाले पर्यटक भी इसी एयरलाइंस की सेवा प्राप्त करते हैं। दिन में केवल एक ही फ्लाइट होने के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है, क्योंकि उसमें कई-कई दिनों तक टिकट नहीं मिलती है और लोगों को टिकट के लिए कईकई दिनों तक वेटिंग में रहना पड़ता है। धर्मशाला के लिए एक फ्लाइट होने के कारण यह एयरलाइंस मनमाना किराया वसूल करती है, कई बार इसका किराया आठ हजार और नौ हजार रुपए तक पहुंच जाता है। मुंबई, बेंगलुरु, आदि अन्य स्थानों की तुलना में धर्मशाला का किराया बहुत अधिक होता है। दिल्ली-धर्मशाला दिल्ली सेक्टर पर किंगफिशर रेड की मोनोपोली बनी हुई है। मेरी सरकार से अनुरोध है कि एक एयरलाइंस की मोनोपोली और यात्रियों की अधिकता को देखते हुए सरकार धर्मशाला के लिए दूसरी एयरलाइंस को भी जल्दी से जल्दी introduce करे, ताकि यात्रियों से उचित किराया ही वसूला जा सके और यात्रियों को कई-कई दिनों की वेटिंग से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद।

Denial of rice allocation to Kerala for festival season

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, I would like to draw the attention of the House to the step-motherly approach of the Central Government to the State of Kerala and the attack of the Central Government to dismantle the Public Distribution System. The Government of Kerala has submitted a memorandum for the allocation of rice under the special quota for Onam festival season. As all of us are aware, Onam is a national festival for Malayalees and the State Government has taken steps to control the price during the festival season. But the approach of the Central Government is totally negative. The Government of India denied the additional allocation beyond the present level of APL allocations. The letter from the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution stated that additional allocation beyond the present level of APL allocation to the State can be made at MSP based issue price of Rs. 10,800 per tonne for wheat and at applicable economic cost for rice. Hence the request for additional allocation of rice and wheat to Kerala on account of Onam festival requirement can be made only at the above price and not at the APL price. This is the letter from the Central Government. Then they can purchase it from FCI godowns at the economic cost of rice, which means Rs. 17.80 per kilogram